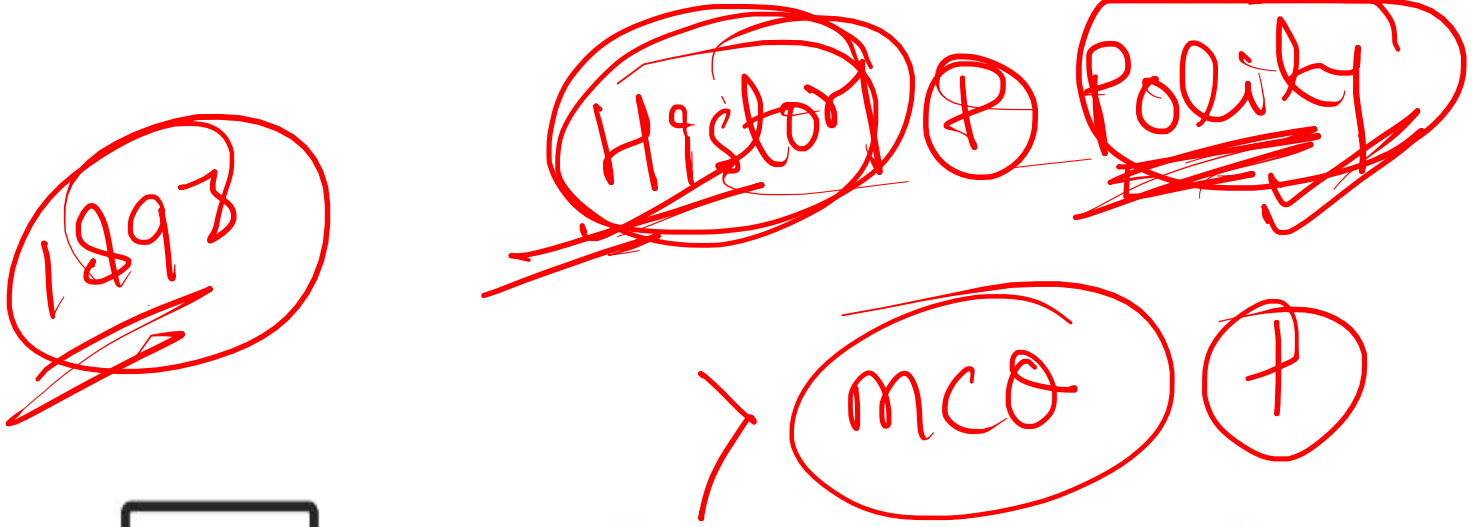

SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

CTET – P-2

SST

INDIAN POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR

Term ⇒ 5 yrs ✗

Pleasure of President

प्रसादपर्यंत

Prime Minister

→ Elected / निर्वाचित (OR) Appointed / नियुक्त

Pres. → Appointed

In the scheme of parliamentary system of government provided by the constitution, the President is the nominal executive authority (de jure executive) and Prime Minister is the real executive authority (de facto executive).

संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकरण (डी ज्यूर कार्यकारी) है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण (वास्तविक कार्यकारी) है ।

Appointment of the Prime Minister

The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the president.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

But, when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the President may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Prime Minister.

लेकिन, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है।

However, if, on the death of an incumbent Prime Minister, the ruling party elects a new leader, the President has no choice but to appoint him as Prime Minister.

हालांकि, अगर किसी मौजूदा प्रधानमंत्री की मौत पर सत्तारूढ़ दल नए नेता का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति के पास उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

In 1997, the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for six months, within which, he should become a member of either House of Parliament; otherwise, he ceases to be the Prime Minister.

१९९७ में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, वह प्रधानमंत्री बने रहते हैं ।

The term of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the president.

However, this does not mean that the president can dismiss the Prime Minister at any time.

So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President.

However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the President can dismiss him.

प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति 2014 में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।

जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता ।

हालांकि अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Collective Responsibility

The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility.

Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

सामूहिक ~~जिम्मेदारी~~ उत्तरदायित्व

सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्यशील मौलिक सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ।

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of ommission and commission.

They work as a team and swim or sink together.

इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों के पास अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है ।

वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं।

The Governor

Appointment, Functions and Powers

राज्यपाल

Head of executive in state

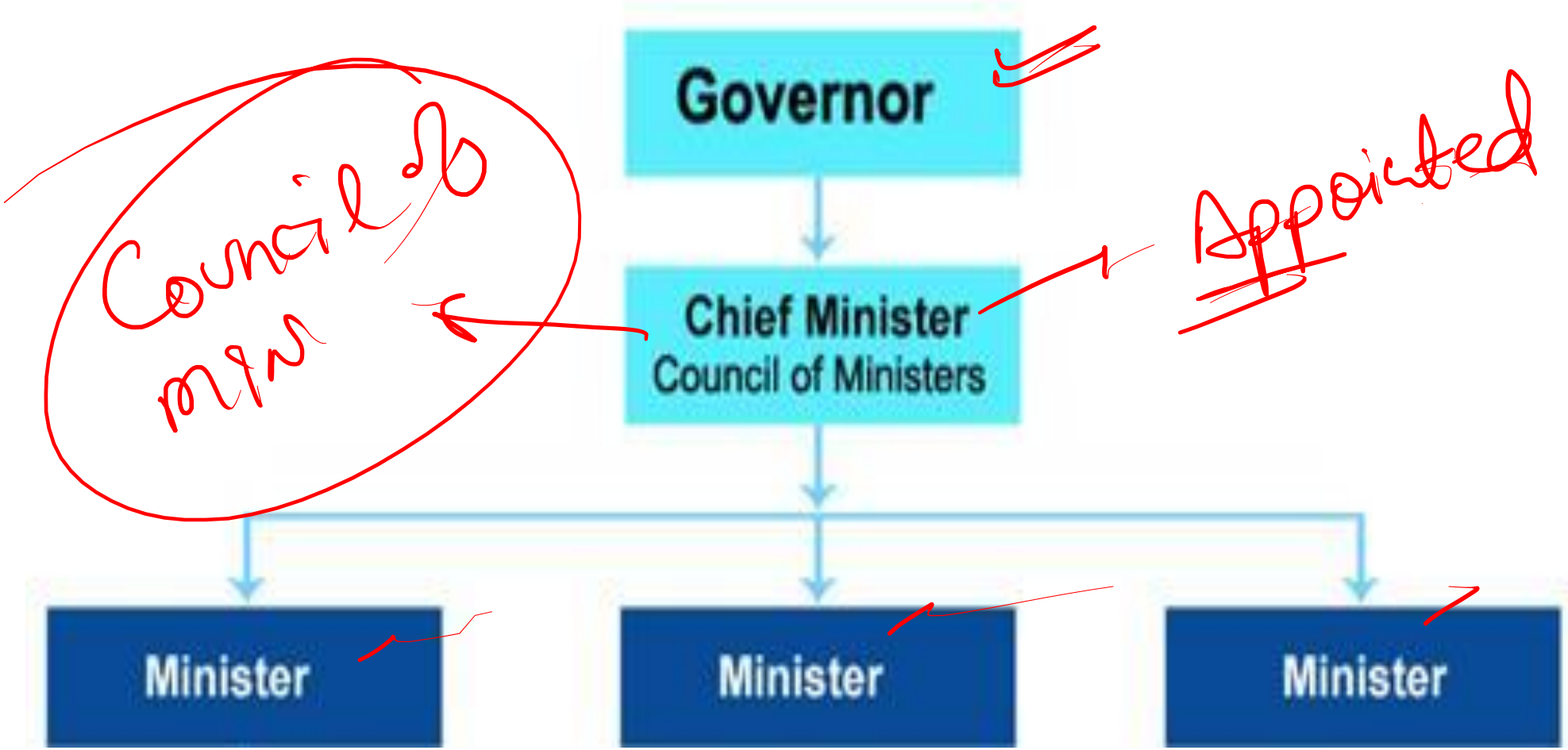
Governor
Chief Minister
Council of Ministers
Minister
Minister
Minister

Articles 153 to 167 in Part VI of the Constitution deal with the state executive.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Appointment of Governor

The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as is the case with the president.

He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. In a way, he is a nominee of the Central government.

राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल न तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है ।

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

एक तरह से वह केंद्र सरकार के उम्मीदवार हैं।

But, as held by the Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the Central government.

It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the Central government.

लेकिन, जैसा कि 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।

यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण में या अधीनस्थ नहीं है।

Term of Governor's Office

A governor holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

However, this term of five years is subject to the pleasure of the President.

Further, he can resign at any time by addressing a resignation letter to the President.

राज्यपाल कार्यालय का कार्यकाल एक राज्यपाल उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय रखता है जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है ।

हालांकि, पांच साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की खुशी के अधीन है ।

अलावा राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र देकर वह ारा कतई भी इस्तीफा दे सकते हैं।

The powers and functions of the governor can be studied under the following heads:

1. Executive powers.
2. Legislative powers.
3. Financial powers.
4. Judicial powers.

1. Executive powers.

1.

He appoints the chief minister and other ministers. They also hold office during his pleasure.

There should be a Tribal Welfare minister in the states of Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him.

1. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

वे अपनी प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करते हैं ।

उनके द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

2.

He appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.

2. वह किसी राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है।

एडवोकेट जनरल राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

3.

He appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.

3. वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उनकी सेवा शर्तों और पद के कार्यकाल का निर्धारण करते हैं ।

हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल समान तरीके से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर हटाया जा सकता है ।

4.

He appoints the chairman and members of the state public service commission.

However, they can be removed only by the president and not by a governor.

4. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है न कि किसी राज्यपाल द्वारा ।

2. Legislative powers.

A governor is an integral part of the state legislature. In that capacity, he has the following legislative powers and functions:

1. **He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly.**

एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उस क्षमता में, उसके पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है ।

2. He can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.

2. वह प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

3. He nominates one-sixth of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service.

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच से राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ।

4. He can nominate one ~~member~~ to the state legislature assembly from the Anglo-Indian Community.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

5.He can promulgate ordinances when the state legislature is not in session.

Art-213

These ordinances must be approved by the state legislature legislature within six weeks from its reassembly.

6M+6W

5. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होता है तो वह अध्यादेश ◌ों◌ं को प्रख्यापित कर सकता है ।

इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी पुनर्विधानसभा से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

Financial Powers

The financial powers and functions of the governor are:

1. **He sees that the Annual Financial Statement (state budget) is laid before the state legislature.**

वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) राज्य विधानमंडल के सामने रखा गया है ।

2. Money bills can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation.

3. No demand for a grant can be made except on his recommendation.

2. राज्य विधानमंडल में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ ही धन विधेयक पेश किए जा सकते हैं।

3. उनकी सिफारिश को छोड़कर अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

4. He can make advances out of the Contingency Fund of the state to meet any unforeseen expenditure.

5. He constitutes a finance commission after every five years to review the financial position of the panchayats and the municipalities

4. वह किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम कर सकता है।

5. वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Judicial Powers

The judicial powers and functions of the governor are:

1.

He can grant pardons, reprives, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends.

न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और कार्य हैं:

1.

वह किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, फटकार, राहत, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण कर सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति फैली हुई है ।

Panchayat Raj
in India

The term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self-government.

It has been established in all the states of India by the Acts of the state legislatures to build democracy at the grass root level.

It is entrusted with rural development. It was constitutionalised through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992.

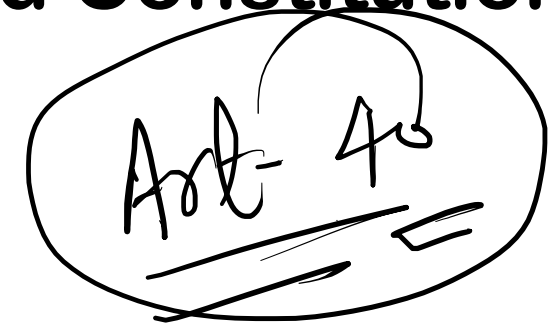

भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का प्रतीक है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा भारत के सभी राज्यों में इसकी स्थापना की गई है ।

इसका जिम्मा ग्रामीण विकास का जिम्मा है।

इसे 1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।

Evolution of Panchayati:

1. Raj Balwant Rai Mehta Committee (Jan-1957)

The committee submitted its report in November 1957 and recommended the establishment of a three-tier panchayati raj system—

gram panchayat at the village level,

panchayat samiti at the block level and

zila parishad at the district level.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

पंचायती राज का विकास:

1. राज बलवंत राय मेहता समिति (जनवरी-1957) समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की-

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और
जिला स्तर पर जिला परिषद।

Rajasthan was the first state to establish Panchayati Raj. The scheme was inaugurated by the prime minister on October 2, 1959, in Nagaur district.

Rajasthan was followed by Andhra Pradesh, which also adopted the system in 1959.

Thereafter, most of the states adopted the system.

पंचायती राज की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया था।

इसके बाद राजस्थान आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में इस व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद ज्यादातर राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया।

Ashok Mehta Committee

In December 1977, the Janata Government appointed a committee on panchayati raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta.

It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations to revive and strengthen the declining panchayati raj system in the country.

अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं को लेकर एक समिति का का गठन किया गया ।

इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें कीं।

Ashok Mehta said The three-tier system of panchayati raj should be replaced by the two-tier system, that is, zila parishad at the district level, and below it, the mandal panchayat consisting of a group of villages.

अशोक मेहता ने कहा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बदलकर जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत गांवों का समूह बनाकर होनी चाहिए।

G V K Rao Committee

The Committee to review the existing Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes under the chairmanship of G.V.K. Rao was appointed by the Planning Commission in 1985.

जी वी के राव समिति जीवीके राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने वाली समिति की नियुक्ति योजना आयोग ने 1985 में की थी।

L M Singhvi Committee

In 1986, Rajiv Gandhi government appointed a committee to prepare a concept paper on 'Revitalisation of Panchayati Raj Institutions for Democracy and Development' under the chairmanship of L M Singhvi.

एल एम सिंघवी समिति

1986 में राजीव गांधी सरकार ने एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की।

Singhvi said The Panchayati Raj institutions should be constitutionally recognised, protected and preserved.

सिंघवी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता, संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

73rd Amendment Act of 1992

This bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 and came into force on 24 April, 1993.

1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम

यह विधेयक अंतत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में उभरा और 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।

This act has added a new Part-IX to the Constitution of India.

This part is entitled as 'The Panchayats' and consists of provisions from Articles 243 to 243 O.

In addition, the act has also added a new Eleventh Schedule to the Constitution.

This schedule contains 29 functional items of the panchayats. It deals with Article 243-G.

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया पार्ट-9 जोड़ा है ।

यह भाग पंचायतों के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान हैं।

इसके अलावा इस अधिनियम में संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है ।

इस शेड्यूल में पंचायतों की 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। यह अनुच्छेद 243-जी से संबंधित है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Reservation of Seats

The act provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in every panchayat (i.e., at all the three levels) in proportion of their population to the total population in the panchayat area.

Further, the state legislature shall provide for the reservation of offices of chairperson in the panchayat at the village or any other level for the SCs and STs.

सीटों का आरक्षण

इस अधिनियम में पंचायत क्षेत्र में कुल आबादी को अपनी आबादी के अनुपात में हर पंचायत (यानी तीनों स्तरों पर) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान है।

इसके अलावा राज्य विधानमंडल में पंचायत में अध्यक्ष के कार्यालयों को गांव में या किसी अन्य स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

The act provides for the reservation of not less than one-third of the total number of seats for women (including the number of seats reserved for women belonging the SCs and STs).

Further, not less than one-third of the total number of offices of chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women.

इस अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के एक तिहाई से कम आरक्षण का प्रावधान है।

इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या का एक तिहाई से भी कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

MUNICIPALITIES OF INDIA

74th Amendment Act of 1992 This Act has added a new Part IX-A to the Constitution of India.

This part is entitled as 'The Municipalities' and consists of provisions from Articles 243-P to 243-ZG.

In addition, the act has also added a new Twelfth Schedule to the Constitution.

This schedule contains eighteen functional items of municipalities. It deals with Article 243-W.

1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग नौवीं-ए जोड़ा है।

यह भाग नगर पालिकाओं के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243-पी से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं ।

इसके अलावा इस अधिनियम में संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है ।

इस अनुसूची में नगरपालिकाओं के अठारह कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-डब्ल्यू से संबंधित है ।

Three Types of Municipalities

The act provides for the constitution of the following three types of municipalities in every state.

1. A nagar panchayat (by whatever name called) for a transitional area, that is, an area in transition from a rural area to an urban area.
2. A municipal council for a smaller urban area.
3. A municipal corporation for a larger urban area.

नगर पालिकाओं के तीन प्रकार इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है।

1. एक नगर पंचायत (जो भी नाम से कहा जाता है) एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, यानी, एक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण में एक क्षेत्र।
2. एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद।
3. एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।

Note → father of local self government in India

स्थानीय स्वशासन ⇓ Ripon रिपन

पहली नगरपालिका

↳ मद्रास

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Judiciary

1947

Supreme Court

1935

[Federal Court]

संघीय न्यायालय

प्रथम न्यायाधीश

M. Gwyer

The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950.

It succeeded the Federal Court of India, established under the Government of India Act of 1935.

However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor.

This is because, the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।

यह भारत के संघीय न्यायालय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित सफल रहा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में बदल दिया है ।

Appointment of Judges

The judges of the Supreme Court are appointed by the president.

The chief justice is appointed by the president after consultation with such judges of the Supreme Court and high courts as he deems necessary.

न्यायाधीशों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

The other judges are appointed by president after consultation with the chief justice and such other judges of the Supreme Court and the high courts as he deems necessary.

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

Qualifications of Judges

A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:

1. He should be a citizen of India.

2. (a) He should have been a judge of a High Court (or high courts in succession) for five years; or

(b) He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years;

न्यायाधीशों की योग्यता

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. (क) उन्हें पांच वर्षों तक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश होना चाहिए था; या

(ख) उन्हें दस वर्षों तक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का अधिवक्ता होना चाहिए था;

or (c) He should be a distinguished jurist in the opinion of the president.

From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court.

या (ग) राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए ।

ऊपर से यह स्पष्ट है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

Tenure of Judges

The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court.

However, it makes the following three provisions in this regard:

1. He holds office until he attains the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament.

न्यायाधीशों का कार्यकाल

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि, यह इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान करता है:

1. वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले। उनकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए इस प्रकार से निर्धारित किया जाना है ।

2. He can resign his office by writing to the president.

3. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament.

2. वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Removal

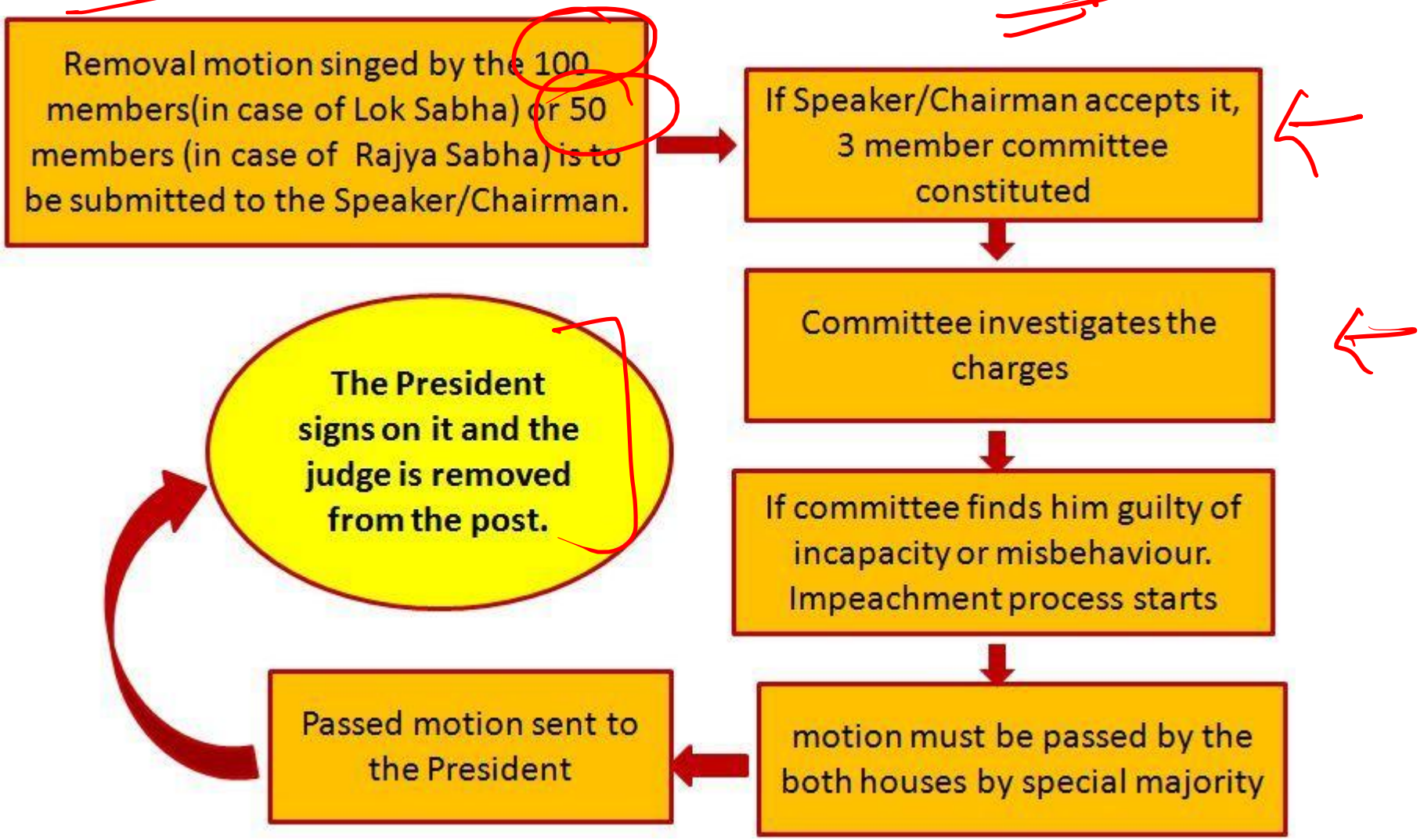

Jurisdiction and Powers of Supreme Court

1. Original Jurisdiction.
2. Writ Jurisdiction.
3. Appellate Jurisdiction.
4. Advisory Jurisdiction.
5. A Court of Record.
6. Power of Judicial Review.
7. Other Powers.

सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां

1. मूल क्षेत्राधिकार।
2. रिट क्षेत्राधिकार।
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार।
5. रिकॉर्ड की एक अदालत ।
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति।
7. अन्य शक्तियां।

1. Original Jurisdiction

As a federal court, the Supreme Court decides the disputes between different units of the Indian Federation. More elaborately, any dispute between:

(a) the Centre and one or more states; or

1. मूल क्षेत्राधिकार

संघीय अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भारतीय महासंघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से, के बीच किसी भी विवाद:

(क) केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य; या

(b) the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or

(c) between two or more states.

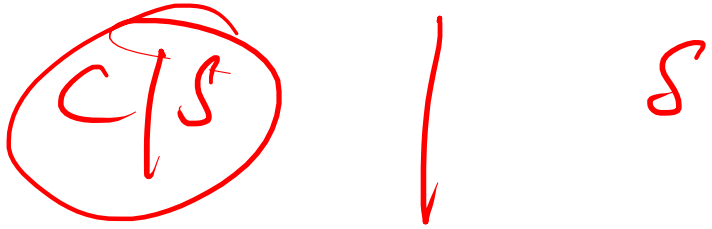

(ख) केंद्र और एक तरफ कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

2. Writ Jurisdiction

Art-32

The Constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental rights of the citizens.

2. रिट क्षेत्राधिकार

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का गठन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में किया है।

3. Appellate Jurisdiction

As mentioned earlier, the Supreme Court has not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal.

The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts.

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने न केवल भारत के संघीय न्यायालय को सफलता दी है बल्कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में भी प्रतिस्थापित किया है ।

सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से अपील की अदालत है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है ।

It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads:

(a) Appeals in constitutional matters.

(b) Appeals in civil matters.

(c) Appeals in criminal matters.

(d) Appeals by special leave.

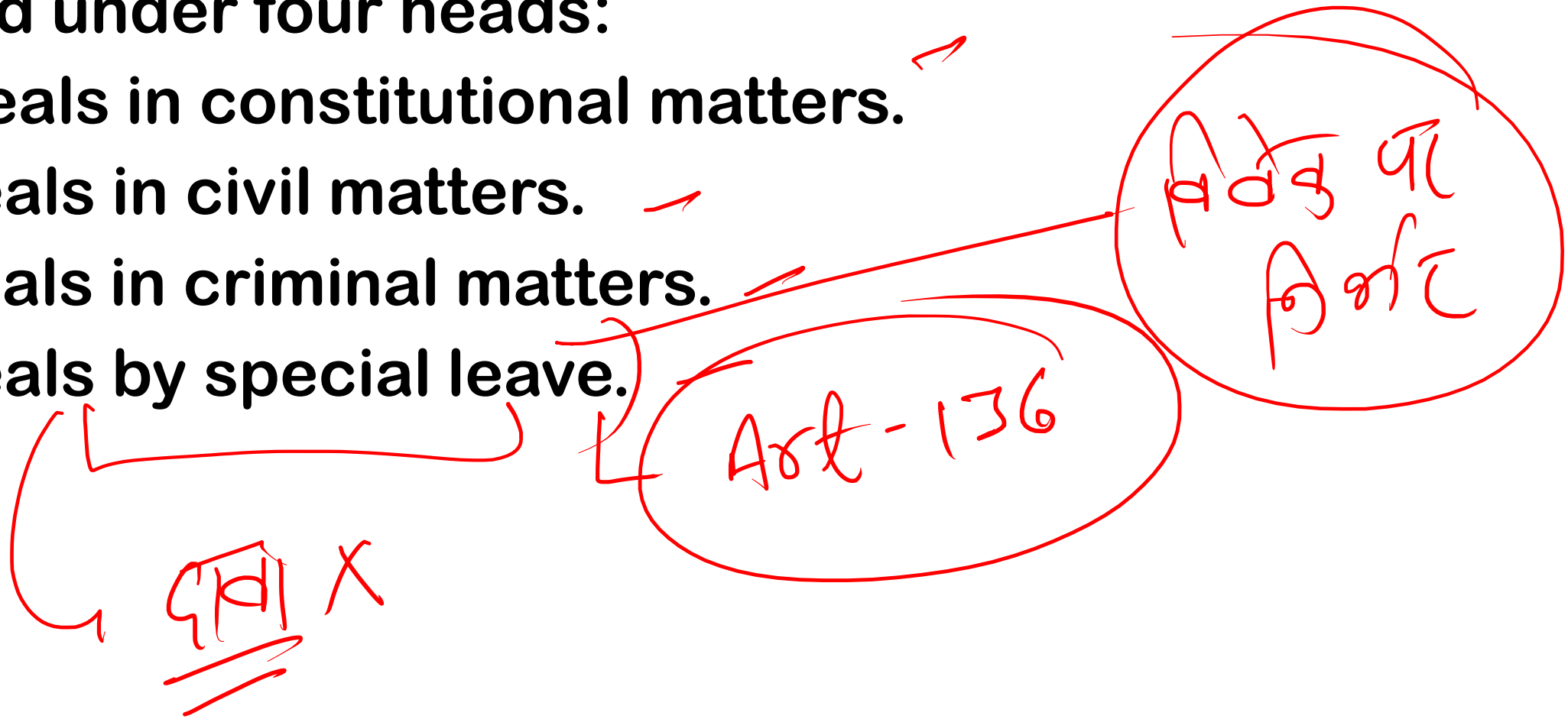

यह एक व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्राप्त है:

(क) संवैधानिक मामलों में अपील।

(ख) सिविल मामलों में अपील ।

(ग) आपराधिक मामलों में अपील।

(घ) विशेष अवकाश द्वारा अपील ।

4. Advisory Jurisdiction

The Constitution (Article 143) authorises the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:

(a) On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.

(b) On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanador other similar instruments

4. सलाहकार क्षेत्राधिकार संविधान (अनुच्छेद १४३)

राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:

(क) कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है ।

(ख) किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, वाचा, सगाई, संयोजिका अन्य समान साधनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर

In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the president. But, in the second case, the Supreme Court 'must' tender its opinion to the president.

In both the cases, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement.

Hence, it is not binding on the president; he may follow or may not follow the opinion.

पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट टेंडर कर सकता है या राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है ।

लेकिन, दूसरे मामले में, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय का टेंडर देना चाहिए ।

दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी है न कि न्यायिक घोषणा। इसलिए, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है; वह का पालन करें या राय का पालन नहीं कर सकते हैं ।

Justice Fathima Beevi became the first female judge who was appointed to the Supreme Court of India in 1989.

25 HC

Articles 214 to 231 in Part VI of the Constitution deal with the organisation, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the high courts.

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, प्रक्रियाएं आदि उच्च न्यायालयों के साथ संबंधित हैं।

The institution of high court originated in India in 1862 when the high courts were set up at Calcutta, Bombay and Madras.

In 1866, a fourth high court was established at Allahabad.

There are 25 High Courts in India.

उच्च न्यायालय की संस्था का उद्भव 1862 में भारत में हुआ था जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी।

1866 में इलाहाबाद में एक चौथा हाईकोर्ट की स्थापना हुई।

भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Read

List of High Courts in India

Year	Name	Territorial Jurisdiction	Seat & Bench
1862	Bombay	Maharashtra Dadra & Nagar Haveli Goa Daman Diu	Seat: Mumbai Bench: Panaji, Aurangabad, and Nagpur
1862	Kolkata	West Bengal Andaman & Nicobar islands	Seat: Kolkata Bench: Port Blair
1862	Madras	Tamil Nadu Pondicherry	Seat: Chennai Bench: Madurai

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Read

1866	Allahabad	Uttar Pradesh	Seat: Allahabad Bench: Lucknow
1884	Karnataka	Karnataka	Seat: Bengaluru Bench: Dharwad and Gulbarga
1916	Patna	Bihar	Patna
1928	Jammu & Kashmir	Jammu & Kashmir	Srinagar and Jammu

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

1948	Guwahati	Assam Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh	Seat: Guwahati Bench: Kohima, Aizawl, and Itanagar
1949	Odisha	Odisha	Cuttack
1949	Rajasthan	Rajasthan	Seat: Jodhpur Bench: Jaipur
1956	Madhya Pradesh	Madhya Pradesh	Seat: Jabalpur Bench: Gwalior and Indore
1958	Kerala	Kerala & Lakshadweep	Ernakulam
1960	Gujarat	Gujarat	Ahmedabad
1966	Delhi	Delhi	Delhi

Read

1971	Himachal Pradesh	Himachal Pradesh	Shimla
1975	Punjab & Haryana	Punjab, Haryana & Chandigarh	Chandigarh
1975	Sikkim	Sikkim	Gangtok
2000	Chattisgarh	Chattisgarh	Bilaspur
2000	Uttarakhand	Uttarakhand	Nainital
2000	Jharkhand	Jharkhand	Ranchi

2013	Tripura	Tripura	Agartala
2013	Manipur	Manipur	Imphal
2013	Meghalaya	Meghalaya	Shillong
2019	Telangana	Telangana	Hyderabad
2019	Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	Amravati

The Constitution of India provides for a high court for each state, but the Seventh Amendment Act of 1956 authorised the Parliament to establish a common high court for two or more states or for two or more states and a union territory.

भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, लेकिन 1956 के सातवें संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया।

Justice Anna Chandy: The First Female High Court Judge Of India

केरल → HC

It is also contested that she is most likely the second woman in the world to become a high court judge after USA's Florence Allen who was appointed as a judge in 1922.

यह भी विरोध किया है कि वह सबसे अधिक संभावना दुनिया में दूसरी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरेंस एलन जो १९२२ में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गई है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Leila Seth

HC के मु० न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी
(HP)

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Leila Seth (20 October 1930 – 5 May 2017) was the first woman judge on the Delhi High Court and she became the first woman to become Chief Justice of a state High Court on 5 August 1991.

लीला सेठ (20 अक्टूबर 1930 - 5 मई 2017) दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला जज थीं और वह 5 अगस्त 1991 को किसी राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनीं।